(time taken - 2h 40 mins)

VISION IAS 16 AUG 2022 M N No. 3 RECEIVED

VISION IAS

www.visionias.in

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 1818)

Name of Candidate	Arpit Kumar		
Medium Eng./Hindi	Hindi	**Registration Number**	546705.
Center	M.N. (Delhi).	**Date**	16/08/22.

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	12.5	
2	12.5	
3	12.5	
4	12.5	
5	12.5	
6	12.5	
7	12.5	
8	12.5	
9	12.5	
10	12.5	
11	12.5	
12	12.5	
13	12.5	
14	12.5	
15	12.5	
16	12.5	
17	12.5	
18	12.5	
19	12.5	
20	12.5	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **ENGLISH & HINDI**
   इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

EVALUATION INDICATORS

1. **Contextual Competence**
2. **Content Competence**
3. **Language Competence**
4. **Introduction Competence**
5. **Structure - Presentation Competence**
6. **Conclusion Competence**

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Answer all the questions in NOT MORE THAN 200 WORDS each. Content of the answers is more important than its length. All questions carry equal marks.

12.5X20=250

1. Explain the meaning of regionalism and highlight the various forms that it can take, with suitable examples from India.

   भारत के संदर्भ में उपयुक्त उदाहरणों के साथ क्षेत्रवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए साथ ही उन विभिन्न रूपों पर प्रकाश डालिए जो इसके द्वारा अपनाए जा सकते हैं।

क्षेत्रवाद से सामान्यत: तात्पर्य व्यक्तियों के समूह द्वारा किसी एक क्षेत्र विशेष के प्रति निष्ठा व्यक्त करना है। अधिकांश मामलों में यह अलगाववादी प्रवृत्तियों को जन्म देता है।

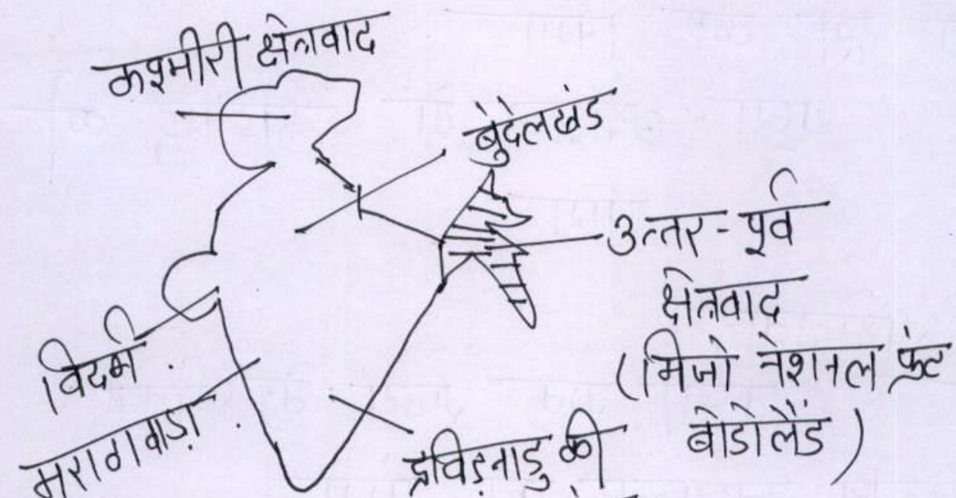

: भारत में क्षेत्रवादी प्रवृत्तियों का सामान्य विवरण·

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रवाद निम्न रूपों में देखा जा सकता है-

I. पृथकतावादी क्षेत्रवाद -

राष्ट्र के अंदर लोगों द्वारा अलग प्रदेश की मांग करना

यथा- ⊙ पंजाब

⊙ बुंदेलखंड राज्य की मांग

II. अलगाववादी क्षेत्रवाद -

राष्ट्र से ही अलग होकर नये देश का निर्माण.

यथा- ⊙ दक्षिण में द्रविड़ नाडु की मांग.

III. उपक्षेत्रवाद :

किसी एक राज्य के भीतर क्षेत्रीय स्वायत्ता की मांग.

यथा- ⊙ बोडोलैंड

⊙ स्वायत्त जिला परिषदें.

आदि.

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

IV. सुप्रा स्टेट क्षेत्रवाद

- ग्रेटर नागालैंड की मांग
- द्रविड़नाडु की मांग

V. अंतर्राज्यीय क्षेत्रवाद

राज्यों के स्तर पर संसाधनों आदि हेतु तीव्र प्रतिस्पर्धा -

"हालांकि क्षेत्रवाद, क्षेत्र के प्रति निष्ठा को व्यक्त करता है किंतु उपराष्ट्रीयताओं का सम्मान करके इसे राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक बनाया जा सकता है।"

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. E-governance is a very vital element in improving public service delivery in India. Discuss with examples.

भारत में सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार के लिए ई-गवर्नेंस एक अत्यधिक महत्वपूर्ण तत्व है। उदाहरण सहित विवेचना कीजिए।

विश्व-बैंक के अनुसार -
ई गवर्नेंस अर्थात शासन के सभी स्तरों पर डिजिटल साधनों का उपयोग करने से है।
यथा- mygov.in पोर्टल

सार्वजनिक सेवा वितरण में ई-गवर्नेंस की महत्ता:

चूंकि भारत 1.4 बिलियन जनसंख्या वाला देश है तथा इसका भौगोलिक आकार भी भौतिक रूप से सेवा वितरण में बाधा पहुंचाता है -

① पारदर्शिता तथा प्रभाविता में वृद्धि.
बायोमीट्रिक (BAPU योजना) के प्रयोग से भारतीय पी.डी.एस. में रिसाव की समस्या दूर हुयी है

तथा लाभार्थियों की बेहतर पहचान सुनिश्चित की जा सकी है।

II. भ्रष्टाचार में लगाम :

सार्वजनिक सेवा वितरण में ई-शासन : पारदर्शिता में वृद्धि करके सामाजिक अंकेक्षण का अवसर प्रदान करता है।

यथा- मनरेगा में मजदूरी वितरण.

III. समस्याओं का तीव्र निस्तारण :

ई-गवर्नेंस ने शिकायत निपटान प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।

कुछ हालिया पहलें :

- mygov.in पोर्टल.
- कर्नाटक - खजाना परियोजना
- मेघदूत परियोजना - मध्यप्रदेश

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

ई-गवर्नेंस की चुनौतियाँ

चुनौतियाँ:
- साइबर सुरक्षा संबंधी चुनौतियाँ
- निम्न डिजिटल साक्षरता (केवल 22% ग्रामीण)
- सरकारी वेबसाइटों का निम्न प्रयोक्ता अनुकूलन
- अवसंरचना की कमी
- पर्याप्त पेशेवर कार्मिकों की कमी

आगे की राह

I. डिजिटल इंडिया अभियान की स्पिरिट को पूर्ण करना
II. डिजिटल गैप को खत्म करना
III. अवसंरचना निर्माण हेतु पी.पी.पी. का सहारा लेना।

"इस प्रकार ई-शासन, सार्वजनिक सेवा वितरण को प्रभावी रूप से सक्षम बनायेगा।"

3. Explain why child labour continues to persist in India, despite stringent measures taken by the government for its eradication.

स्पष्ट कीजिए कि भारत में सरकार द्वारा बाल श्रम के उन्मूलन के लिए किए गए कठोर उपायों के बावजूद, यह अभी भी क्यों जारी है।

भारत द्वारा आई. एल. ओ. के अभिसमय 182 तथा 138 को हस्ताक्षरित किया गया है, किंतु अभी भी भारत में बाल श्रम विद्यमान है.

सरकार द्वारा किये गये कठोर उपाय

- संवैधानिक प्रावधानों का क्रियान्वयन (अनु. 23, 24)
- बाल श्रम निषेध अधिनियम
  - 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा काम पर रोक
- बाल अधिकार आयोग की स्थापना
- (14-18) वर्ष के बच्चों को हानिकारक कार्यों पर प्रतिबंध
- (PENCIL) पोर्टल को प्रारंभ करना.

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार प्रत्येक 3 बाल श्रमिकों में से एक बच्चा भारतीय होता है -

कारण :

1. आर्थिक :
- गरीब परिवारों में आय की सुरक्षा न होना.
- सामाजिक सुरक्षा जाल का मजबूत न होना.
- चक्रीय निर्धनता की स्थिति में बाल श्रम में बढोत्तरी.

II. सामाजिक :
- बालिकाओं की शिक्षा की उपेक्षा (पितृसत्तात्मक सोच)
- कुछ कार्यों में बालकों की उपयुक्तता.
  - शिवकाशी में माचिस उद्योग
  - कश्मीर में कालीन उद्योग

III. कानूनी

- राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग का प्रभाविता से कार्य करना.
- बाल श्रम निषेध अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन न होना.

आगे की राह·

→ प्रभावी समष्टिगत आर्थिक नीतियों को लागू करना
॥
गरीबी दूर करना

→ शिक्षा का अधिकार आदि का प्रभावी क्रियान्वयन

→ कानूनी ढाँचे को मजबूत करना.

"बाल श्रम, सभ्य समाज पर कलंक की भाँति होता है, इसके तत्काल उन्मूलन हेतु हेतु प्रयास किये जाने चाहिए"

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. It is argued that the role of women in family often remains unrecognised. In this context, do you think wages for housework is an idea whose time has come?

यह तर्क दिया जाता है कि परिवार में महिलाओं की भूमिका को प्रायः मान्यता नहीं मिलती है। इस संदर्भ में, क्या आपको लगता है कि गृहकार्य के लिए वेतन के विचार को अपनाने का समय आ गया है?

भारत का पारिवारिक ढाँचा पितृसत्तात्मकता से ग्रस्त रहा है, जहाँ पुरुष निर्णयकर्ता की भूमिका में होते हैं व महिलाएँ अनुगामी के रूप में।

परिवार में महिलाओं की दोयम भूमिका.

I. आई.एल.ओ. के अनुसार 2/3 घरेलू कार्य भारतीय महिलाओं द्वारा.

II. निर्णय प्रक्रिया से वंचित होना

III. शिक्षा, स्वास्थ्य में पुरुषों की अपेक्षा द्वितीय स्तर.
(भारतीय महिलाएँ - गर्भधारण के उम्र की - 50% अनीमिक)

गृहकार्य के लिए वेतन का विचार.

समाजशास्त्रियों के एक वर्ग का यह मानना रहा है कि गृहकार्य के लिए वेतन देने से यह महिला सशक्तीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि करेगा.

लाभ
- → महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार
- → चयन की स्वतंत्रता का उपभोग करने में सक्षम
- → परिवार में समानता का दर्जा.
- → निर्णयकर्ता की भूमिका में आने का अवसर.
- → पुरुष - स्त्री समानता का विचार

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

चुनौतियाँ -

- आकलन करने की कोई सर्वमान्य पद्धति का न होना
- महिलाओं पर दोहरा बोझ
  - घरेलू कार्य
  - वैतनिक कार्य

'इस दिशा में सशक्त विचार-विमर्श आवश्यक है हालांकि तब तक घरेलू कार्य को सम्मान का दर्जा अवश्य दिया जाना चाहिए।'

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. Highlight the role of the Right To Information (RTI) Act, 2005 in ensuring transparency and good governance in India.

भारत में पारदर्शिता और सुशासन सुनिश्चित करने में सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 की भूमिका पर प्रकाश डालिए।

सूचना का अधिकार अधि. 2005 भारतीय लोकतंत्र की महती उपलब्धि थी जिसने नागरिकों के सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया -

RTI और पारदर्शिता

I. सिविल सोसायटी के डोमेन में सूचना तक पहुँच

II. गोपनीयता की जगह पारदर्शिता की संस्कृति.

III. अधिकांश कार्यवाहियों, मानकों, संसाधनों का प्रकटीकरण.

IV. नागरिकों द्वारा RTI आवेदनों के द्वारा सूचना की मांग.

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

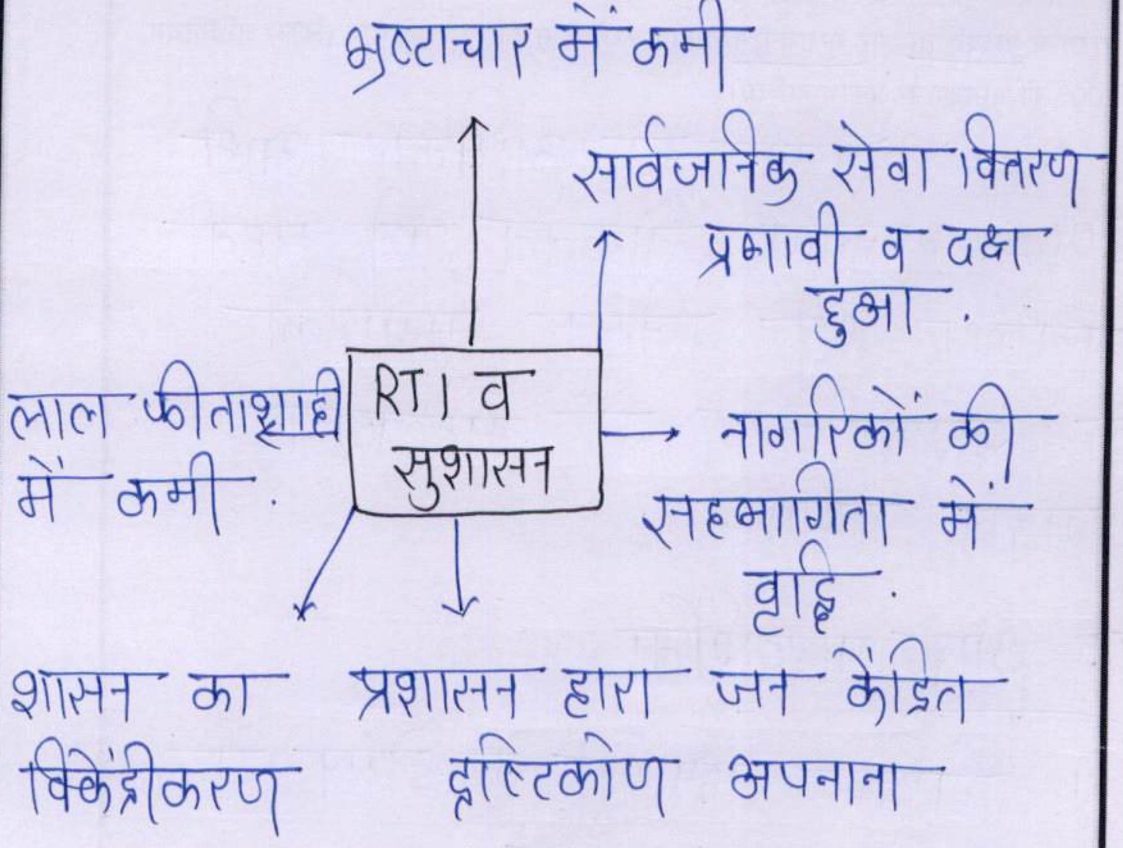

हालांकि सूचना का अधिकार अधिनियम की इस सफलता के बावजूद इस दिशा में कई चुनौतियाँ विद्यमान हैं-

1. ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी.

II. डिजिटल अवसंरचना की कमी.

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

III. सूचनाओं के प्रकटीकरण में अधिकारियों में संकोच की भूमिका.

IV. पी. आई. ओ. में प्रशिक्षण की समस्या।

"इन समस्याओं को लक्षित करके सूचना का अधिकार अधि. को और प्रभावी बनाया जा सकता है।"

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. Explain the reasons behind growing mental health issues faced in India. State the policy measures taken in this regard as well.

भारत में बढ़ती मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारणों की व्याख्या कीजिए। इस संबंध में अपनाए गए नीतिगत उपायों का भी उल्लेख कीजिए।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार- मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य, व्यक्ति का अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करने से है।

भारत में मानसिक स्वास्थ्य, एक उपेक्षित विषय रहा है, जिसे अक्सर बीमारी का दर्जा भी नहीं दिया जाता रहा है.

कारण -

1. बढ़ता उपभोक्तावाद -

भौतिकतावादी जीवन शैली में आत्म संतुष्टि न होना अंत में मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

II. कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन.

लैन्सेट की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 ने बच्चों तथा युवाओं में मानसिक अवसाद को और गहरा किया है।

III. शैक्षणिक पाठ्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य न होना.

भारतीय समाज में मानसिक स्वास्थ्य, मुख्य धारा का विषय नहीं रहा है।

IV. नैदानिक उपचार व्यवस्था का अभाव.

भारतीय ग्रामीण इलाकों व सब-अर्बन सिटीज में उपचार अवसंरचना का न होना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

नीतिगत उपाय :

I. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NIMHANS)

II. टेली-मेडिसिन की शुरुआत

III. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में मानसिक स्वास्थ्य प्रभाग की शुरुआत।

IV. मानसिक स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन।

" वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति के द्वारा समन्वयपूर्ण तरीके से इस ओर प्रयास किये जाने चाहिए। "

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. Enumerate the measures taken for population control in India. Also, discuss whether there is a need for a new Population Policy in India.

भारत में जनसंख्या नियंत्रण के लिए किए गए उपायों को सूचीबद्ध कीजिए। साथ ही, चर्चा कीजिए कि क्या भारत में एक नई जनसंख्या नीति की आवश्यकता है।

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग के अनुसार, भारत 2025 तक चीन को पीछे छोड़ सर्वाधिक जन-संख्या वाला देश बन जाएगा।

जनसंख्या नियंत्रण के उपाय:

- 1938- अंतरिम सरकार द्वारा प्रयास.
- 1967 - परिवार नियोजन कार्यक्रमों की शुरुआत.
- 1975- नसबंदी कार्यक्रम
- 2000- राष्ट्रीय जनसंख्या नीति
  ⇓
  2045 तक स्थिर जनसंख्या तथा जनांकिकीय लाभांश प्राप्त करना.
- गर्भनिरोधक उपायों को प्रोत्साहित करना.

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

हालांकि इन उपायों के बावजूद भारत विश्व की 17%. जनसंख्या का निवास स्थान है.

नयी जनसंख्या नीति की आवश्यकता.

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति-2000, पुरानी पड़ चुकी है तथा आधुनिक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम नहीं है.

① नयी नीति के द्वारा भारत जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में नये लक्ष्य बना सकेगा।

II. शिक्षा तथा स्वास्थ्य आदि पर खर्च के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास.

III. जनसंख्या नियंत्रण में क्षेत्रीय

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

विषमताओं (उत्तर-दक्षिण) को दूर करना।

IV. प्रतिस्थापन दर, सभी राज्यों में लाना।

"इस प्रकार एक समग्र जनसंख्या नीति के द्वारा भारत इसका जनांकिकीय लाभांश लेने में भी समर्थ हो सकेगा॥"

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. What do you understand by secularism in the context of India? Explain how secularism is reflected in our constitutional provisions.

भारत के संदर्भ में पंथनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए कि हमारे संवैधानिक उपबंधों में पंथनिरपेक्षता कैसे परिलक्षित होती है।

"भारतीय संदर्भ में पंथ-निरपेक्षता से तात्पर्य, राजनीति का धर्म से पृथक्करण तथा विभिन्न धर्मों के मध्य स्वतंत्रता व समानता से है"

भारतीय पंथनिरपेक्षता की विशे:-

I. पश्चिम के विपरीत अंतर धार्मिक तथा अंतः धार्मिक दोनों समानता

II. राज्य द्वारा प्रगामी मूल्यों की स्थापना हेतु सक्रिय हस्तक्षेप.

III. राज्य द्वारा समान रूप में समुदाय के कल्याण हेतु सहायता का उपबंध।

धार्मिक समानता

⇑

अनु. 14, 15, 16, 17

मूल अधिकार

- अनु. 14, 15, 16, 17 ⇒ धार्मिक समानता
- अनु. 19 ⇒ धार्मिक स्वतंत्रता
- अनु. 25, 26
- अनु. 27, 28 ⇒ अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकार

⇑

संवैधानिक उपबंध ⇒ प्रस्तावना
- विचार, अभिव्यक्ति विश्वास की स्वतंत्रता.

⇓

नीति-निदेशक तत्व.

⇓

समान नागरिक संहिता का उपबंध

"भारतीय संविधान के उपबंधों के साथ भारतीय राज्य व्यवहार में भी पंथनिरपेक्षता का अनुसरण करता है।"

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. Discuss the role played by SHGs in rural development in India. Also, mention various measures which have been taken by the government to promote SHGs in India.

भारत में ग्रामीण विकास में एस.एच.जी. (SHGs) द्वारा निभाई गई भूमिका की विवेचना कीजिए। साथ ही, भारत में एस.एच.जी. को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों का उल्लेख कीजिए।

स्वयं सहायता समूहों से तात्पर्य समान उद्देश्य तथा साझा हितों की पूर्ति हेतु संगठित हुये लोगों के समूह से है।

ग्रामीण विकास में निभायी गयी भूमिका -

I. स्वयं सहायता समूहों ने गाँवों को स्वावलंबी बनाने में मुख्य ~~ग्रामी~~ कार्य किया.

II. पितृसत्ता की जड़ें तोड़ने में प्रभावी रहे हैं।

III. महिलाएँ आर्थिक रूप से सशक्त हुयी हैं तथा निर्णयकारी भूमिका प्राप्त की है।

iv. वर्तमान में 45 मिलियन महिलायें एस. एच. जी. (S.H.G.) में संलग्न हैं तथा लगभग 1,86,000 करोड़ रु का संचालन करती हैं।

v. SHG- बैंक लिंकेज कार्यक्रम ने ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की उपलब्धता में वृद्धि की है जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव गरीबी निवारण में दिखा है।

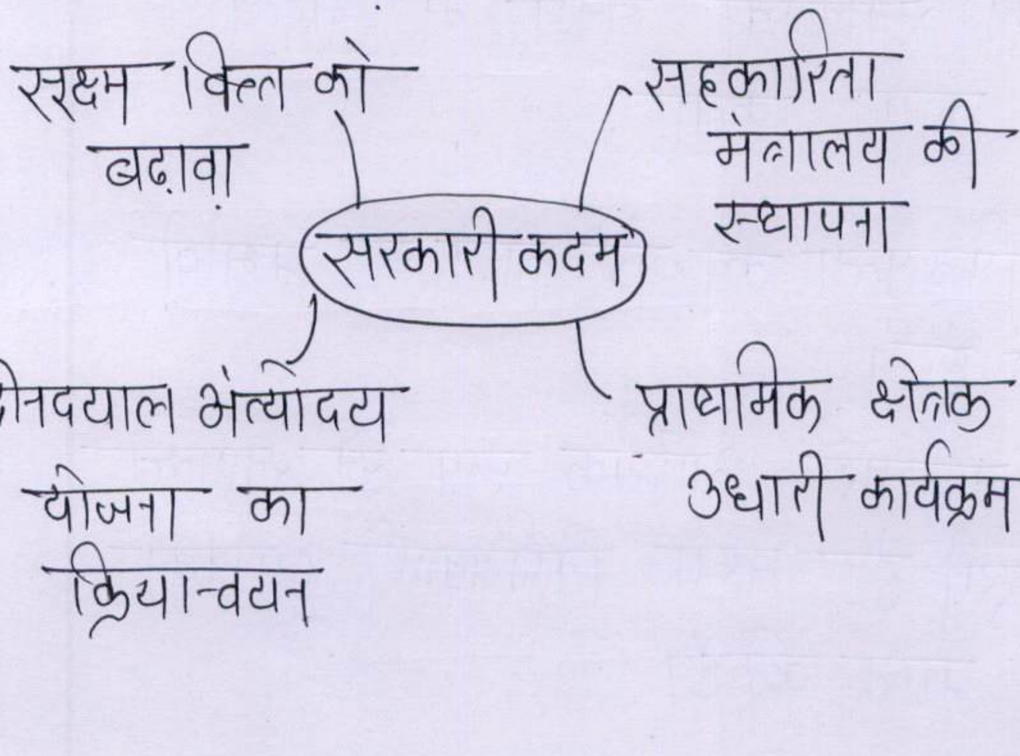

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

"इस प्रकार, स्वयं सहायता समूह ग्रामीण स्वावलंबन तथा महिला सशक्तीकरण दोनों में सहायक साबित हो रहे हैं।"

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. What are the various challenges being faced by school going children in India in light of the ongoing COVID-19 pandemic?

वर्तमान में जारी कोविड-19 महामारी के आलोक में, भारत में स्कूल जाने वाले बच्चों द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न चुनौतियां कौन-सी हैं?

भारत में कोविड-19 के संकट का सामना करने के क्रम में विश्व का सबसे बड़ा लॉकडाउन आरोपित रहा तथा सर्वाधिक समय हेतु भारतीय स्कूल बंद रहे हैं।

बच्चों द्वारा सामना की जा रही चुनौतियाँ :

विद्यालय परिसर में :

- ग्रामीण तथा सब अर्बन सिटी में विद्यालयों में नव अवसंरचना का अभाव
  - सोशल दूरी
  - सैनिटेशन
  - मास्क की उपलब्धता

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- छात्र तथा अध्यापक संपर्कों में नए मानकों को अपनाना.
- लंबे अंतराल के बाद विद्यालयों का खुलना जिससे बच्चों का इसके अनुकूल न हो पाना.
- खेल-कूद आदि बाह्य गतिविधियों का प्रभावित होना.

अन्य चुनौतियां
- → बच्चों में डिजिटल डिवाइड कायम होना
- → विभिन्न विद्यालयों के मध्य असमानता (निजी - सरकारी)
- → बच्चों में अवसाद का आना.
- → समाज के नकारात्मक माहौल में उनकी सृजनात्मकता प्रभावित.

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

आगे की राह:

- कोविड-19 अनुकूल अवसंरचना विकास.
- शिक्षकों को नये मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण.
- नवाचारों को अपनाना.

"इन उपायों के द्वारा बच्चों को स्कूल में अनुकूल वातावरण प्रदान किया जा सकेगा।"

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

11. Identify the barriers faced by Persons with Disabilities (PwDs) in India. What measures have been taken by the government in this context?

भारत में दिव्यांगजनों (PwDs) के सामने आने वाली बाधाओं की पहचान कीजिए। इस संदर्भ में, सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

भारतीय जनगणना, 2011 के अनुसार भारत में 2.2% दिव्यांग जनसंख्या है।

सामना की जाने वाली बाधाएँ -

1. सार्वजनिक सहभागिता में समस्या -
भारत का सार्वजनिक ढाँचा, दिव्यांगों के अनुकूल नहीं है
यथा - रेलों, बसों आदि में दिव्यांग अनुकूल अवसंरचना का अभाव।
खेल - कूद के मैदानों में उनको नजरअंदाज करना।

II. राजनीतिक सहभागिता -
अपनी 2.2% जनसंख्या के

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

मुकाबले संसद तथा विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व नगण्य के बराबर है-

III. सामाजिक वंचना, उपेक्षा-

संवेदना की बजाय भारतीय गाँवों, शहरों में विव्योंग उपहास तथा मजाक का विषय बनते हैं।

IV. आर्थिक वंचना:

रोजगार के अवसरों की अनुपलब्धता की वजह से वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हैं।

सरकारी उपाय:

1. सुगम्य भारत अभियान:

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

सुगम्य भारत अभियान, अवसंरचना में सुधार करके, दिव्यांगों की सहभागीता में वृद्धि सुनिश्चित करेगा।

ii. शैक्षणिक तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण

इस कदम से दिव्यांगजन सामाजिक तथा आर्थिक रूप से सशक्त हो सकेंगे।

"सरकारी उपायों के साथ-साथ सामाजिक मनोवृत्तियों में परिवर्तन, दिव्यांग सशक्तीकरण को सुनिश्चित करेगा।"

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

12. Examine whether the relationship between civil services and democracy is complementary or paradoxical.

परीक्षण कीजिए कि क्या लोक सेवाओं और लोकतंत्र के बीच संबंध पूरक है या विरोधाभासी?

लोक सेवाओं से तात्पर्य स्थायी कार्यपालिका से है जो सार्वजनिक नीतियों का क्रियान्वयन संभव बनाती है -

लोक सेवाओं और लोकतंत्र के मध्य संबंधों की प्रकृति

पूरक के रूप में

- लोगों द्वारा चुनी गयी सरकार के एक अंग के रूप में राजनीतिक प्रतिनिधियों को सहायता प्रदान करना।
- खुली प्रतियोगिता के माध्यम से लोक सेवकों का चयन : लोकतंत्र की भूमिका

- चुनी गयी सरकार के पूरक के रूप में कार्य करना.
- शासन को स्थायित्व प्रदान करना.
- जनता की समस्याओं व आकांक्षाओं को समझना.

विरोधी के रूप में:
- नौकरी की स्थायित्व प्रवृत्ति.
- सामंती मानसिकता
- अभिजात्यवाद का हावी होना.
- स्थायी कार्यपालिका.

निष्कर्षत: यह शासन का रूप तय करता है कि लोक सेवाएँ लोकतंत्र की सहभागी बनेगीं या विरोधी यथा.

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

भारत में लोक सेवाएँ लोकतंत्र की सहभागी हैं.
वहीं चीन में परस्पर विरोधी।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

13. What are the obstacles faced in the implementation of various e-governance initiatives in India? Provide some feasible suggestions to overcome these obstacles.

भारत में विभिन्न ई-गवर्नेंस पहलों के कार्यान्वयन में किन बाधाओं का सामना करना पड़ता है? इन बाधाओं को दूर करने के लिए कुछ व्यावहारिक सुझाव दीजिए।

ई-गवर्नेंस से तात्पर्य शासन के स्तरों पर डिजिटल साधनों का उपयोग करना है।

भारतीय ई-गवर्नेंस पहलें -
- डिजिटल इंडिया
- माई गवर्नमेण्ट (mygov.in)
- मेघदूत परियोजना
- अन्य सरकारी परियोजनाएँ.

बाधाएँ :

सामुदायिक :
- भारत में डिजिटल साक्षरता का कम होना
  ⇒ केवल २२% ग्रामीण महिला साक्षरता

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- सरकारी वेबसाइटों की प्रयोक्ता अनुकूलता का कमजोर होना
- सरकारी कार्मिकों के मध्य प्रशिक्षण का अभाव

संस्थागत

- डिजिटल अवसंरचना का अभाव (कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का अभाव)
- ग्रामीण डिजिटल कनेक्टिविटी का अभाव.

तकनीकि

- साइबर सुरक्षा अवसंरचना का मजबूत न होना.
- साइबर अटैक

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

बाधाओं को दूर करने के व्यावहारिक सुझाव

- निजी क्षेत्र की सहायता से सरकारी वेबसाइटों की प्रयोज्यता बढ़ाना
- सरकारी सेवकों को डिजिटल प्रशिक्षण देना.
- भारत नेट परियोजना के माध्यम से ग्रामीण कनेक्टिविटी
- नवाचारों हेतु डिजिटल हैकाथॉन आयोजित करना.

"ई-गवर्नेंस भारत में शासन की प्रभाविता बढ़ाने में क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है"

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

14. What are the challenges faced by India's primary healthcare system? Mention the government initiatives to address these challenges.

भारत की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां कौन-सी हैं? इन चुनौतियों के समाधान हेतु सरकार की पहलों का उल्लेख कीजिए।

भारत, अपनी जी.डी.पी. का मात्र 1.6% प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च करता है।

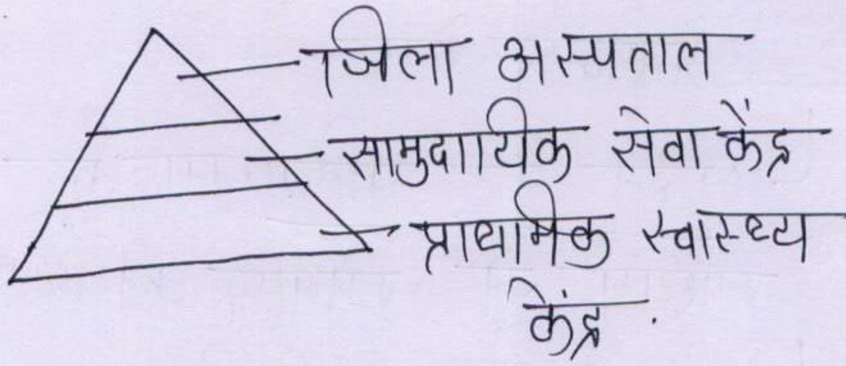

चुनौतियाँ:
- अवसंरचना का अभाव (संस्थागत प्रसव हेतु उपकरणों आदि का अभाव)
- पर्याप्त पेशेवर चिकित्सकों का न होना
- चिकित्सा मानकों का ध्यान न रखना

- ग्रामीण क्षेत्रों के दूर-दराज इलाकों तक पहुँच न होना.
- सेवा डिलीवरी में असक्षमता.
- द्वितीयक स्वास्थ्य कार्मिकों का अभाव.
- रिफर केंद्रों के रूप में उदय.

सरकारी पहलें:

I. बजट का एक निश्चित भाग प्राथमिक स्वास्थ्य पर खर्च करना.

II. मंडल स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मॉडलों का विकास करना.

III. डॉक्टरों को फील्ड वर्क के रूप में कुछ वर्षों की बाह्य सेवा

आदि

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

"इस प्रकार एक उपयुक्त राष्ट्रीय नीति के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में सुधार किया जा सकता है।"

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

15. Giving an account of the initiatives taken by the government for urban development in recent years, explain how they seek to solve some of the major problems of urbanization faced in India.

हाल के वर्षों में सरकार द्वारा शहरी विकास के लिए प्रारंभ की गई पहलों का विवरण देते हुए, स्पष्ट कीजिए कि ये भारत में शहरीकरण की कुछ प्रमुख समस्याओं के समाधान हेतु कैसे प्रयास करती हैं।

यू. एन. वर्ल्ड हैबिटाट के अनुसार 2047 तक भारत की दो तिहायी जनसंख्या शहरों में निवास करेगी.

शहरी विकास हेतु पहलें :

I. प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना.
- वर्ष 2015 में प्रारंभ.
- वर्ष 2022 तक नगरीकरण का लक्ष्य

II. अमृत योजना (AMRUT).
- शहरों में जलापूर्ति तथा जलनिकासी की व्यवस्था.
- सीवेज ट्रीटमेंट
- मलिन बस्तियों का समाधान

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

III. स्मार्ट सिटीज.

· वर्ष 2015 में प्रारंभ
· वैज्ञानिक तरीकों से 100 शहरों का विकास.

IV. स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)

· वर्ष 2014 में प्रारंभ.
· ODF तथा ODF+ मानकों को हासिल करना।

V. हृदय योजना.

· शहरों की संस्कृति का परिरक्षण को बढ़ावा.
· टूरिज्म (पर्यटन) को बढ़ावा देना
विरासत संरक्षण.

इन योजनाओं द्वारा निम्न प्रकार से शहरी समस्याओं का

प्रबंधन संभव है।

समाधान

- स्वच्छ भारत मिशन – मलिन बस्तियों की समस्या
  - पर्यावरण तथा स्वास्थ्य लाभ।
- स्मार्ट सिटीज ⇒ वैज्ञानिक नगरीय ढाँचा
- आवास योजना ⇒ मलिन बस्तियों का निपटान।
- अमृत योजना ⇒ शहरों में बेहतर जल प्रबंधन।
  - जल प्रदूषण का समाधान
- हृदय योजना - भारतीय संस्कृति का संरक्षण।

"भारत के तीव्र नगरीकरण को देखते हुये इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होगा।"

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

16. Highlighting the general deficiencies in implementation of citizen's charters in India, enumerate the measures required to make them an effective tool of enhancing accountability in governance.

भारत में नागरिक चार्टरों के कार्यान्वयन में सामान्य कमियों को रेखांकित करते हुए, इन्हें शासन में जवाबदेही बढ़ाने का एक प्रभावी उपकरण बनाने के लिए आवश्यक उपायों को सूचीबद्ध कीजिए।

नागरिक चार्टर: सुशासन की अवधारणा कि रूप में एक जन केंद्रित पहल है -

नागरिक चार्टर
- संगठन का उद्देश्य
- प्रदान की जाने वाली योजनाएं
- समयावधि
- गुणवत्ता मानक
- शिकायत निवारण अधिकारी

कार्यान्वयन में कमियाँ

1. विभिन्न संगठनों के चार्टरों के मध्य अतिव्यापन.

प्रभावी प्रकटीकरण न होना

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

II. नागरिक चार्टर तैयार करते समय सामान्य मानकों का पालन न करना.

III. गुणवत्ता के बारे में जानकारी का अभाव

IV. शिकायत निपटान प्रणाली का प्रावधान नहीं होना.

जवाबदेही बढाने हेतु आवश्यक उपाय.

I. नागरिक चार्टर तैयार करते समय सिविल सोसायटी की सहायता लेना.

II. आवधिक निरीक्षण सुनिश्चित करना.

III. संपूर्ण देशभर की सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करना।

IV. क्रियान्वयन में डिजिटल शासन का सहारा लेना.

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

v. सूचना का अधिकार अधिनियम तथा सोशल ऑडिट की भी सहायता लेना।

"इस प्रकार बेहतर व प्रभावी नागरिक चार्टर, सुशासन हेतु आवश्यक तत्व हैं।"

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

17. Differentiating between absolute and relative poverty, give an account of the progress made by India in eradicating poverty in recent decades, with adequate data and examples of government interventions.

निरपेक्ष और सापेक्ष निर्धनता के मध्य अंतर स्पष्ट करते हुए, पर्याप्त आंकड़ों और सरकारी हस्तक्षेपों के उदाहरणों के साथ, हाल के दशकों में भारत द्वारा निर्धनता उन्मूलन की दिशा में की गई प्रगति का विवरण दीजिए।

अमर्त्य सेन के अनुसार -
"क्षमताओं का अभाव गरीबी है।"

निरपेक्ष गरीबी	सापेक्ष गरीबी
⊙ न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति न होना. यथा - आहार तक पहुँच न होना.	⊙ शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन शैली आदि के मानकों पर जनसंख्या के दो वर्गों के मध्य की तुलनात्मक स्थिति.
⊙ गरीबी का निकृष्टतम रूप.	

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

भारत में निर्धनता उन्मूलन की दिशा में प्रगति

I. भारत में 1994 से 2012 के मध्य गरीबी प्रतिशत 45 से 22% पर आ गया है।

II. हालांकि वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक गरीब 364 मिलियन भारत में निवास करते हैं।

III. भारत, निर्धनता को समग्र रूप से लक्षित कर रहा है-

यथा- शिक्षा
स्वास्थ्य
अवसरों तक पहुँच

IV. हालांकि, कोविड-19 ने इस प्रगति को बाधित किया है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

"वर्तमान में भारत को आवश्य-
-कता है कि कोविड-19 प्रेरित
गरीबी को दूर करते हुये संस्थागत
रूप से ~~निर्धार~~ निर्धनता को
लक्षित करे।"

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

18. Analyse the changes that have taken place in the traditional joint family system in India in recent decades.

हाल के दशकों में भारत में पारंपरिक संयुक्त परिवार प्रणाली में हुए परिवर्तनों का विश्लेषण कीजिए।

भारतीय पारिवारिक ढाँचा संयुक्त परिवार का रहा है। जिसमें परिवार के सभी सदस्य साथ में रहते हैं-

संयुक्त परिवार प्रणाली में परिवर्तन-

औद्योगीकरण-

औद्योगीकरण ने कृषि की जनसंख्या को आकर्षित किया है। जिससे संयुक्त परिवार प्रणाली कमजोर हुयी है-

रोजगार तथा शिक्षा के अवसर-

बेहतर रोजगार, आय तथा शिक्षा की चाह में भारतीय युवक बड़े शहरों की ओर आकर्षित

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

हुये हैं

नगरीकरण का प्रभाव

भारतीय पारिवारिक प्रणाली तीव्र नगरीकरण का सामना कर रही है। स्वमेव रूप में यह एकल परिवार को प्रेरित कर रही है।

वैश्वीकरण का प्रभाव

भारतीय संस्कृति, पश्चिमी मूल्यों को भी आत्मसात कर रही है। जिसके फलस्वरूप लिव-इन परिवार, एकल महिला मुखिया परिवार सामने आये हैं।

वैवाहिक मूल्यों में परिवर्तन

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

वर्तमान में प्रेम विवाहों को स्वीकृति भी एकल परिवार में वृद्धि कर रही है।

निष्कर्षतः भले ही भारत में संयुक्त परिवारों का प्रचलन कम हुआ है किंतु संपत्ति तथा त्योहार आदि अवसरों पर यह संयुक्तता कायम है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

19. Discuss the vulnerabilities faced by the elderly in India and highlight some steps taken by the government to address these.

भारत में वृद्धजनों द्वारा सामना की जाने वाली सुभेद्यताओं पर चर्चा कीजिए और इनके निवारण हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदमों को रेखांकित कीजिए।

सामाजिक सुरक्षा जाल की अप्रभाविता, भारत में वृद्धजनों की सुभेद्यताओं को बढा रही है-

वृद्धजनों की सुभेद्यताएँ

- आश्रय का संकट
  - भारत में बढते वृद्धाश्रम
- स्वास्थ्य का संकट
  - युवा पीढी द्वारा वृद्धजनों के स्वास्थ्य खर्चों को वहन न करना.
- आजीविका तथा आय का संकट
- दुर्व्यवहार की समस्या
  - गरिमा पर चोट

इन सुभेद्यताओं के साथ-2 परिवार से दूर होना इनमें गुणात्मक वृद्धि करता है।

सरकारी कदम

- राष्ट्रीय वयोश्री योजना
  - बीपीएल श्रेणी से संबंधित वृद्धों की सहायता
- SAGE पोर्टल का प्रारंभ
- वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना
  - सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित
- प्रधानमंत्री वय वंदना योजना
- अन्नपूर्णा योजना
- वृद्ध व्यक्तियों हेतु एकीकृत कार्यक्रम
  - आश्रय
  - भोजन
  - चिकित्सा देखभाल आदि

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

'वृद्धों का सम्मान भारतीय मूल्य प्रणाली की विशेषता रही है, जिसका पुनर्जीवन इन सुभेद्यताओं के निवारण हेतु आवश्यक है।"

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

20. With the help of suitable examples, examine the impact of globalization on environment.

उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से पर्यावरण पर वैश्वीकरण के प्रभाव का परीक्षण कीजिए।

वैश्वीकरण से तात्पर्य व्यक्तियों, वस्तुओं, सरकारों तथा पर्यावरण का अंतर्संबंधित होना है।

पर्यावरण पर वैश्वीकरण के प्रभाव.

1. वस्तुओं तथा प्रदूषकों के परिवहन में वृद्धि -
   - खतरनाक रसायनों का सीमा-पार आवागमन (रॉटरडैम अभिसमय)
   - समुद्र में तेल रिसावों की घटना
   - आक्रामक प्रजातियों की उपस्थिति
   - ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन आदि
   - ओजोन परत का संकट

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

जैव विविधता पर प्रभाव

वैश्विक तापन, महासागरीय अम्लीकरण, वनों की कटाई आदि ने जैव विविधता को नकारात्मक तरीके से प्रभावित किया है।

III. विकासशील देशों के संसाधनों का दोहन

चीन द्वारा अफ्रीका तथा अफगानिस्तान के संसाधनों का दोहन.

IV. उत्पादों की खपत में वृद्धि

बढ़ते उपभोक्तावाद से पारिस्थितिकी दोहन का संकट कायम हुआ है।

हालांकि इन नकारात्मक प्रभावों के साथ-साथ वैश्वीकरण

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

के कुछ सकारात्मक प्रभाव भी सामने आये हैं -

- लोगों के मध्य सहयोग (विभिन्न एन. जी. ओ.)
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (कॉप 26 रामसर अभिसमय)

"जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वैश्वीकरण के लाभ अधिक से अधिक हों तथा हानियाँ कम से कम।"